JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

कृषि साख में किसान क्रेडिट कार्ड की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन

सुजीत कुमार सिंह[1]

डॉ0 अभिषेक पाण्डेय[2]

[1] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ0 एस0एम0एन0आर0 विश्वविद्यालय, लखनऊ
[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ0 एस0एम0एन0आर0 विश्वविद्यालय, लखनऊ

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निवासियों के अस्तित्व और विकास का सम्बन्ध कृषि क्षेत्र से आदिकाल से जुड़ा है। आधारिक व्यवसाय एवं अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति का क्षेत्र होने के कारण सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह अपरिहार्य है। यह समस्त मानव जाति के लिए जीवन का आधार है। विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक निर्भरता के कारण कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि का राष्ट्रीय आय, रोजगार एवं उत्पादन में सापेक्षिक योगदान अपेक्षाकृत कम है। परन्तु विकासशील एवं अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास का आधार ही कृषि है। इसी अनुरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार कृषि है।

भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तम्भ होने के बावजूद भी वित्तीय समस्याओं से जूझ रही है। किसानों की वित्तीय समस्याओं हेतु सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ की। इस योजना में, किसानों को आवश्यकतानुसार साख की उपलब्धता तत्कालीन समय पर करायी जाती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि में वृद्धि के साथ–साथ किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। परन्तु व्यवहार में, क्या ऐसा हो रहा है? या महज एक सैद्धान्तिक सफलता है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन्ही तथ्यों की समीक्षा होगी तथा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत शोध पत्र की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

[1] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ0 एस0एम0एन0आर0 विश्वविद्यालय, लखनऊ
[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ0 एस0एम0एन0आर0 विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोध का उद्देश्य

शोध कार्य के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिन्दु में बंधित किया जा रहा है :–

1. भारतीय कृषि में कृषि साख की महत्ता पर प्रकाश डालना।
2. किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति एवं कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करना।
3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वन में कौन–कौन सी व्यावहारिक समस्याएं है, का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनायें

प्रस्तुत शोध कार्य के सम्पादन हेतु प्रस्तावित परिकल्पनाएँ न्मिनलिखित है :–

1. **H_0** : किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर सार्थकता स्तर पर स्थिर पाई जाती है।

   H_1 : किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर सार्थकता स्तर पर परिवर्तनशील पाई जाती है।
2. **H_0** : किसान क्रेडिट द्वारा मंजूरी राशि की संवृद्धि दर समयानुसार सार्थकता स्तर पर स्थिर पाई जाती है।

   H_1 : किसान क्रेडिट द्वारा मंजूरी राशि की संवृद्धि दर समयानुसार सार्थकता स्तर पर स्थिर पाई जाती है।

शोध प्रणाली

प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि पर आधारित है। शोध कार्य हेतु आवश्यक तथ्य एवं आंकड़े, द्वितीयक प्रकृति के है। **द्वितीयक तथ्य एवं आंकड़ों का संकलन** RBI Various Annual Year Publication Report of Trend and Progress of Banking in India से किया गया है। आंकड़ें परिणात्मक प्रकृति के है। प्रस्तुत शोध में परिकल्पना की जांच के लिए संवृद्धि दर का प्रयोग किया गया है। जो निम्न सूत्र से ज्ञात कर एफ परीक्षण तथा पी परीक्षण के आधार पर जांची गई है।

$$Y = e^{(a+b^T)}$$

जहां $Y =$ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या अथवा मंजूरी राशि है। $T =$ समय, $a =$ स्थिरांक, $b =$ संवृद्धि दर।

भारतीय कृषि में कृषि साख की महत्ता

पारम्परिक कृषि में, कृषि कार्य प्रायः स्वनिर्मित एवं श्रमप्रधान तकनीको की सहायता से हो जाता था, इससे कृषि में बिना पूँजी के भी उत्पादन संभव हो जाता था, परन्तु कालान्तर में बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। उत्पादकता बढ़ाने हेतु, कृषि में पूँजी प्रधान

संसाधनों, जैसे–ट्रैक्टर, सिंचाई के उपकरण, उर्वरक, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि में वित्त की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। दूसरी ओर कृषि के व्यवसायीकरण एवं विविधीकरण के परिणामस्वरूप भी कृषि में वित्त की माँग बढ़ गयी है, साथ ही साथ कृषि की कुछ आंतरिक सीमाओं के कारण यह अन्य उद्योगों की भांति ज्यादा आंतरिक बचतें भी नहीं कर पाती है। इसलिए कृषि को वित्त के लिए वाह्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। निष्कर्षःत वर्तमान समय में कृषि कार्य बिना वित्त के सुचारू रूप से नहीं चल सकता है।

कृषकों को उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने, मजदूरी और लगान का भुगतान करने, भूमि में आधारित सुधार करने, विभिन्न उपभोग वस्तुओं की प्राप्ति एवं पुराने ऋणों के परिशोधनार्थ वित्त की आवश्यकता होती है। अधिकांश कृषक अपने निजी चालू आय स्रोतों द्वारा कृषिगत उक्त आवश्कताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि साख की समस्या का उदय होता है। नियोजन के पूर्व कृषि का स्वरूप मूलतः परस्परावादी रहा। फलतः कृषि साख की आवश्यकता कम थी और उसकी आपूर्ति मुख्यतः निजी स्रोतों से हो जाती थी। नियोजन काल में विशेषकर कृषि की नवीन तकनीक के प्रादुर्भाव के फलस्वरूप कृषि साख की माँग में विभिन्न नवीन निवेशों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन हो गया है।

सामान्य रूप से कृषि साख की माँग तीन प्रकार की होती है : खेती के चालू खर्चों यथा बीज, उर्वरक, मजदूरी आदि के लिए अल्पकानीन साख की आवश्यकता होती है। इसकी अवधि सामान्यतः 15 महीने तक होती है। कृषि के लिये उपयोगी पशु एवं कृषि उपकरण खरीदने तथा कुओं और बांधों की मरम्मत के लिये मध्यम कालीन ऋण की आवश्यकता होती है इसकी अवधि सामान्यतः 3 से 5 वर्ष होती है तथा भूमि खरीदने, भूमि को कृषि योग्य बनाने, कुओं एवं बाँधों के निर्माण व अधिक कीमत वाले कृषियंत्रों को खरीदने के लिए दीर्घकालीन साख की आवश्यकता होती है। इसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक होती है। कृषि और सम्बद्ध क्रियाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों से साख आपूर्ति होती है।

प्रारम्भ में कृषक कृषि वित्त के लिए, गैर संस्थागत स्रोतो, जिनमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, जमींदार एवं सम्बन्धी आते है, पर निर्भर थे। वित्त के ये स्रोत ऋण प्रदान करने में सरल प्रक्रिया अपनाते है, परन्तु इनकी प्रकृति शोषणात्मक होती है। इनके शोषण से किसानों को बचानें के लिए सरकार स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को संस्थागत स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराया जाय। इसके लिए सरकार बहुसस्थान और बहु ऋण उत्पाद की नीति पर प्रयास कर रही है। बहुसंस्थान की नीति पर सरकार ने सहकारी, साख संगठन, भूमि विकास बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के साथ ही वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उनकों अपने कुल स्वीकृत साख का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र को देना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि साख के संस्थागत स्रोतों पर नियन्त्रण हेतु सरकार ने 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रमीण विकास बैंक {नाबार्ड}' नाम से ग्रामीण साख की एक सर्वोच्च संस्था की स्थापना की।

कृषि साख की समस्या के समाधान हेतु नाबार्ड द्वारा उठाये गये कदम

ग्रामीण साख की सर्वोच्च बैंक नाबार्ड कृषि वित्त की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। नाबार्ड किसानों को सीधे सहायता प्रदान नही करता है, बल्कि सहकारी संस्थाओ, व्यापारिक बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में नाबार्ड द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे है:–

a. नाबार्ड संस्थागत स्रोतों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है।
b. ग्रामीण अधोसंरचना विकास फंड {RIDF} - ''राज्य सरकारों तथा सरकारों के अधीन कार्यरत निगमों को, विभिन्न ग्रामीण आधारित परियोजनाओं को पूरा करने हेतु, आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए की {RIDF} स्थापना 1995–96 में किया गया। वर्तमान में इसकी पूँजी 50 हजार करोड़ है।
c. लघु वित्त क्षेत्र में नूतन प्रयोग – निर्धन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लघु वित्त संस्थाओं के माध्यम से नाबार्ड प्रयास कर रहा है।
d. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
e. पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण

नाबार्ड वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण काय कार्य भी करती है, जिससे वे सुचारू रूप से काम करें और किसानों को आपेक्षित लाभ प्रदान करें।

संस्थागत स्रोतों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना वित्तीय सहायता के लिये बैंकिंग योजना है। इसी पर शोधकर्त्ता ने अपने शोध कार्य केन्द्रित किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना {KCCS}

किसान क्रेडिट कार्ड योजना {KCCS} वर्ष 1998–99 में प्रारम्भ की गयी। यह एक बैंकिग योजना है, जिस पर नियन्त्रण एवं निर्देशन का कार्य रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड करती है। इस योजना में किसानों को उनकी अल्पकालिक कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्रदान करने की सुविधा है। योजना के अंतर्गत किसानों की भू–धारकता एवम् फसल चक्र {खसरा एवं खतौनी} के आधार पर एक उच्चतम ऋण सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। इस सीमा के अंदर, किसान आवश्यकतानुसार जितनी बार चाहे बैंक से भुगतान ले सकता है। KCCS तीन वर्ष तक वैध होता है। परन्तु प्रत्येक वर्ष पूर्व में लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान करना पड़ता है। KCCS के चालू होने से किसान अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, जोताई, सिंचाई आदि के लिए आदि के लिए ऋण लेते है। अब किसान की निर्भरता सूदखोरों/साहूकारों पर नही रह गयी है। KCCS ने साहूकारों के उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति एवं कार्य निष्पादन

1) समयानुसार किसान क्रेडिट कार्ड का विश्लेषण

किसान क्रेडिट कार्ड का विश्लेषण यदि समयानुसार देखें तो 2006 से लेकर 2019 तक क्रमशः वृद्धि का क्रम पाया जाता है। परन्तु 2009–10 में इसमें वृद्धि की गति अत्यधिक तेज थी। 2011 में इसकी प्रगति में रूकावट आई जो 2012 तक बनी रही। तालिका 1 और चित्र 1 में स्पष्ट है कि 2006 में जहां कुल किसान क्रेडिट कार्ड की निर्गमन संख्या 80.12 लाख थी। वह 2019 में बढ़कर 663 लाख हो गई परन्तु इस क्रम में उच्चावचन भी आये है। जैसे 2006 से 2008 तक कुल निर्गमन संख्या लगभग 80 लाख के आस–पास बनी रही। जो 2009 में बढ़कर 846.67 लाख हो गई और 2010 में 936.73 लाख हो गई। परन्तु इसके बाद इसमें गिरावट की स्थिति आई और 2011 में यह गिरकर 176.04 लाख पाई गई। पुनः 2012 में गिरावट आई और यह 117.60 पर सिमट गई। 2013 से इसमें पुनः वृद्धि का क्रम देखा जा सकता है जो 129.82 लाख से बढकर 2017 में 714.74 लाख हो गई। 2017 से 2019 में पुनः गिरावट का क्रम पाया गया। 2006 से 2019 तक औसतन 377.91 लाख कार्ड निर्गमित किये गये। जिसमें विचरणता की माप 78.19 बनी है। यदि संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 16.3 प्रतिशत पाई जा रही है।

तालिका 1 : समयानुसार किसान क्रेडिट कार्ड धारको की संख्या : भारत के संदर्भ में

Value in lakhs

Year	Coop.	RRB	Com	Total	% in total of Coop	% in total of rrb	% in total of Comm	
2006	25.98	12.49	41.65	80.12	32.43	15.59	51.98	
2007	22.98	14.06	37.67	74.70	30.76	18.82	50.42	
2008	20.91	17.72	34.36	72.99	28.65	24.28	47.07	
2009	361.45	114.71	370.51	846.67	42.69	13.55	43.76	
2010	378.88	134.21	423.64	936.73	40.45	14.33	45.23	
2011	46.03	31.64	98.37	176.04	26.15	17.97	55.88	
2012	29.61	19.95	68.04	117.60	25.18	16.96	57.86	
2013	26.91	20.48	82.43	129.82	20.73	15.78	63.50	
2014* (drag values)	121.19	53.51	149.22	276.93	43.76	19.32	53.88	
2015* (drag values)	122.76	55.26	146.71	262.07	46.84	21.09	55.98	
2016* (drag values)	124.34	57.00	144.19	247.21	50.30	23.06	58.33	

2017	358.83	122.71	233.20	714.74	50.20	17.17	32.63	
2018	334.95	121.93	235.21	692.10	48.40	17.62	33.98	
2019	304.14	122.53	236.32	663.00	45.87	18.48	35.64	
Average	162.78	64.16	164.39	377.91				
SD	138.3838	44.82128	113.7141	295.5003				
COV	85.01165	69.86061	69.17182	78.19344				
CAGR	19.21037	17.71248	13.20153	16.29317				
Growth								

स्रोत : RBI Various Annual Year Publication Report of Trend and Progress of Banking in India

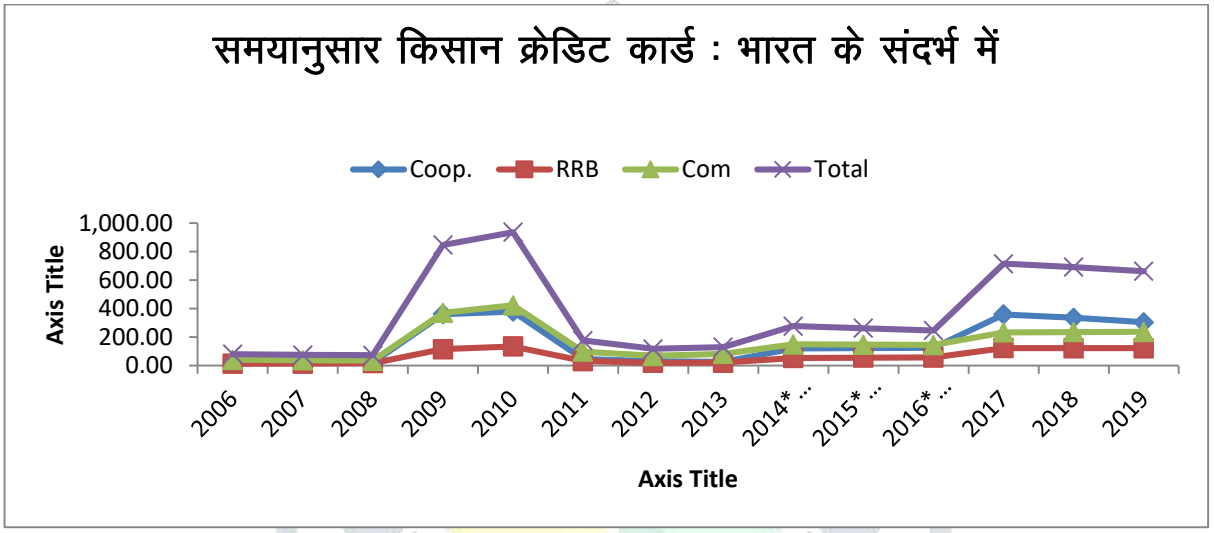

चित्र 1 : समयानुसार किसान क्रेडिट कार्ड : भारत के संदर्भ में

किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर की जांच

H_0: किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर सार्थकता स्तर पर स्थिर पाई जाती है।

H_1: किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर सार्थकता स्तर पर परिवर्तनशील पायी जाती है।

तालिका 2, 3 एवं 4 तथा चित्र 2 क्रमशः इकाई स्वतंत्रता के मान (d.o.f.) तथा 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर संवृद्धि दर 0.13 या 13 प्रतिशत पाई गई है। इसकी जांच एफ–परीक्षण के आधार पर की गई है। जिसका मान 5.806 तथा प्रायिकता मान 0.33 है जो $p < 0.05$ है। अतः स्पष्ट है कि संवृद्धि मॉडल सही हैं एवं इसका स्वरूप निम्न प्रकार से है–

$$KCC_1 = e^{(4.577+0-0.130T)}$$

$$S.E. \qquad (0.458) \qquad (0.54)$$

$$t \qquad (9.995) \qquad (2.410)$$
$$p \qquad (0.000) \qquad (0.033)$$

स्थिरांकों के टी–परीक्षण के प्रायिकता मान (जो 0.05 से कम हैं) से स्पष्ट है कि एवं सार्थक मान हैं तथा आर–वर्ग का मान 0.326 या 32.6 प्रतिशत जो स्पष्ट करता है कि समयानुसार परिवर्तन का प्रभाव निर्गमन पर 32.6 प्रतिश पड़ रहा है।

अतः प्रथम शून्य परिकल्पना, "किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर सार्थकता स्तर पर स्थिर पाई जाती है" को अस्वीकृत किया जा रहा हैं तथा वैकल्पिक परिकल्पना– "किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर सार्थकता स्तर परिवर्तनशील पायी जाती है" को स्वीकृत किया जा रहा है।

तालिका 2 : किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर के सम्बन्ध में मॉडल सारांश

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.571	.326	.270	.811

तालिका 3 : किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर के सम्बन्ध में अनोवा परिणाम

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.821	1	3.821	5.806	.033
Residual	7.897	12	.658		
Total	11.718	13			

तालिका 4 : किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर के सम्बन्ध में मॉडल स्थिरांकों का मान एवं परीक्षण मान

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Case Sequence	.130	.054	.571	2.410	.033
(Constant)	4.577	.458		9.995	.000
The dependent variable is ln(Total_Card).					

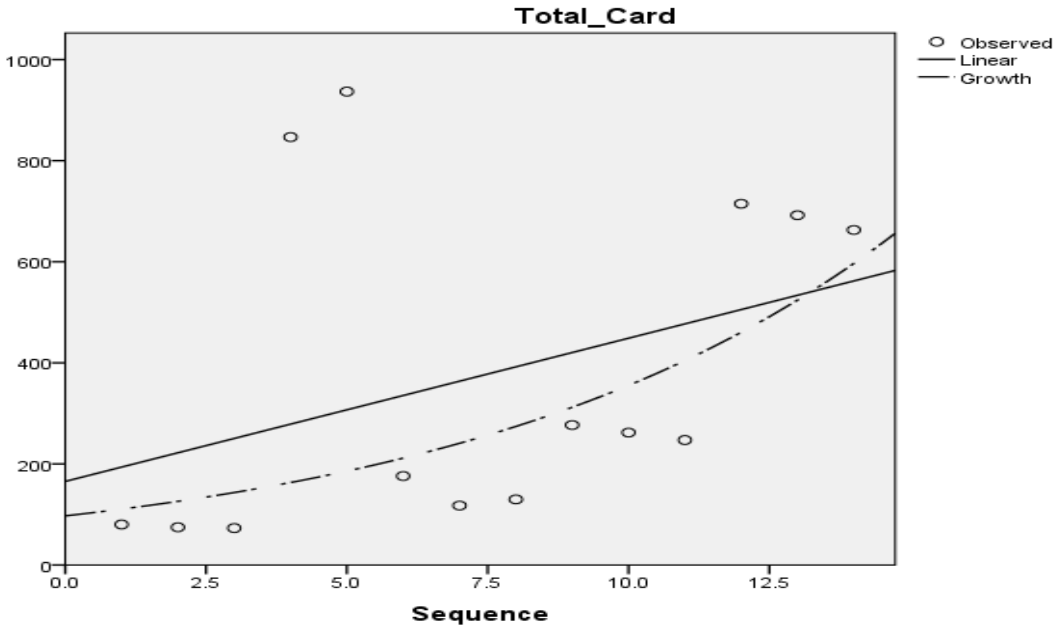

चित्र 2 : किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गमन की वृद्धि दर का चित्रिय प्रदर्शन

समान समयावधि अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड में मंजूरी राशि का क्रम निरन्तर बढ़ता रहा है। परन्तु इसमें भी थोड़ा उच्चावचन देखा जा सकता है। जो पूर्णतः किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन श्रेणी के अनुसार है। 2006 में कुल मंजूरी राशि 476 अरब थी जो 2007 में घटकर 402.9 अरब राशि हो गई। 2008 से पुनः इसमें वृद्धि की गई। और 2009–10 में इस वृद्धि का क्रम अत्यधिक तीव्र बना रहा जो 4277 अरब तक पहुंच गया। 2011–12 में यह राशि घट गई और 916 अरब पर पाई गई। 2013 से 2019 तक पुनः इसमें वृद्धि का क्रम पाया गया। 1262.7 अरब से बढ़कर 7095.8 अरब पहुंच गया। इस पूरी अवधी में औसतन 2637.89 अरब की राशि को मंजूरी मिली जो 77.81 विचरणता की माप पर पाई गई। संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 21.28 प्रतिशत पाई गई। (तालिका 5, चित्र 3)

तालिका 5 : समयानुसार मंजूरी राशि : भारत के संदर्भ में

Value in billion

Year	Coop.	RRB	Com	Total	% in total of Coop	% in total of rrb	% in total of Comm	Total %
2006	203.3937	85.8253	187.7947	476.0137	42.73	18.03	39.45	100.21
2007	131.4065	73.7315	197.8578	402.9958	32.61	18.30	49.10	100.00
2008	199.9127	87.4246	198.9973	486.3346	41.11	17.98	40.92	100.00
2009	1329.882	438.323	1932.495	3700.701	35.94	11.84	52.22	100.00

2010	1405.94	539.64	2331.9	4277.48	32.87	12.62	54.52	100.00
2011	164.5251	158.7427	780.3682	1103.636	14.91	14.38	70.71	100.00
2012	106.4	115.15	695.0697	916.8	11.61	12.56	75.81	99.98
2013	119.2086	132.6374	1010.91	1262.756	9.44	10.50	80.06	100.00
2014* (drag values)	417.7032	249.4726	1473.606	2140.781	19.51	11.65	68.83	100.00
2015* (drag values)	408.8409	259.5923	1597.313	2265.746	18.04	11.46	70.50	100.00
2016* (drag values)	399.9786	269.7119	1721.02	2390.71	16.73	11.28	71.99	100.00
2017	1122	1024.2	1581.1	3727.4	30.10	27.48	42.42	100.00
2018	1244.848	1133.639	4304.739	6683.226	18.63	16.96	64.41	100.00
2019	1274.36	1270.718	4550.791	7095.869	17.96	17.91	64.13	100.00
Average	609.17	417.06	1,611.71	2,637.89				
SD	492.2961	389.5238	1276.948	2052.553				
COV	80.81406	93.39805	79.2293	77.81043				
CAGR	14.00538	21.22785	25.57002	21.28673				

स्रोत : RBI Various Annual Year Publication Report of Trend and Progress of Banking in India

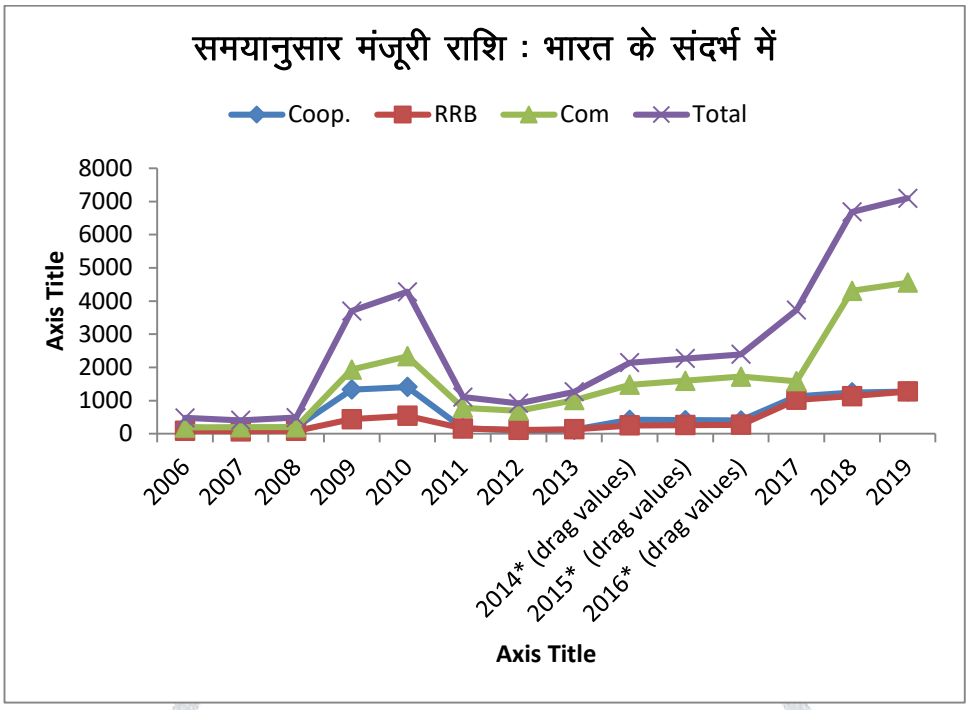

चित्र 3 : समयानुसार मंजूरी राशि : भारत के संदर्भ में

किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी राशि की वृद्धि दर की जांच

H_0 : किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मंजूरी राशि की संवृद्धि दर समयानुसार सार्थकता स्तर पर स्थिर पाई जाती है।

H_1 : किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मंजूरी राशि की संवृद्धि दर समयानुसार सार्थकता स्तर पर परिवर्तनशील पाई जाती है।

तालिका 6, 7 तथा 8 एवं चित्र 4 क्रमशः इकाई स्वतंत्रता के मान (d.o.f.) तथा 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर संवृद्धि दर 0.18 या 18 प्रतिशत पाई गई है। इसकी जांच एफ–परीक्षण के आधार पर की गई है। जिसका मान 17.057 तथा प्रायिकता मान 0.001 है जो $p < 0.05$ है। अतः स्पष्ट है कि संवृद्धि मॉडल सही हैं एवं इसका स्वरूप निम्न प्रकार से है–

$$KCC_2 = e^{(6.172+0.177)}$$

$$\begin{array}{lll} S.E. & (0.364) & (0.043) \\ t & (16.939) & (4.130) \\ p & (0.000) & (0.001) \end{array}$$

स्थिरांकों के टी–परीक्षण के प्रायिकता मान (जो 0.05 से कम हैं) से स्पष्ट है कि एवं सार्थक मान हैं तथा आर–वर्ग का मान 0.587 या 58.7 प्रतिशत जो स्पष्ट करता है कि समयानुसार परिवर्तन का प्रभाव निर्गमन पर 58.7 प्रतिशत पड़ रहा है।

अतः द्वितीय शून्य परिकल्पना, किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मंजूरी राशि की संवृद्धि दर समयानुसार सार्थकता स्तर पर स्थिर पाई जाती है" को अस्वीकृत किया जा रहा हैं तथा वैकल्पिक परिकल्पना– किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा मंजूरी राशि की संवृद्धि दर समयानुसार सार्थकता स्तर पर परिवर्तनशील पाई जाती है।

तालिका 6 : किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी राशि की वृद्धि दर के सम्बन्ध में मॉडल सारांश

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.766	.587	.553	.645

तालिका 7 : किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी राशि की वृद्धि दर के सम्बन्ध में अनोवा परिणाम

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.107	1	7.107	17.057	.001
Residual	5.000	12	.417		
Total	12.106	13			

तालिका 8 : किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी राशि की वृद्धि दर के सम्बन्ध में मॉडल स्थिरांकों का मान एवं परीक्षण मान

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Case Sequence	.177	.043	.766	4.130	.001
(Constant)	6.172	.364		16.939	.000
The dependent variable is ln(Total_Amount).					

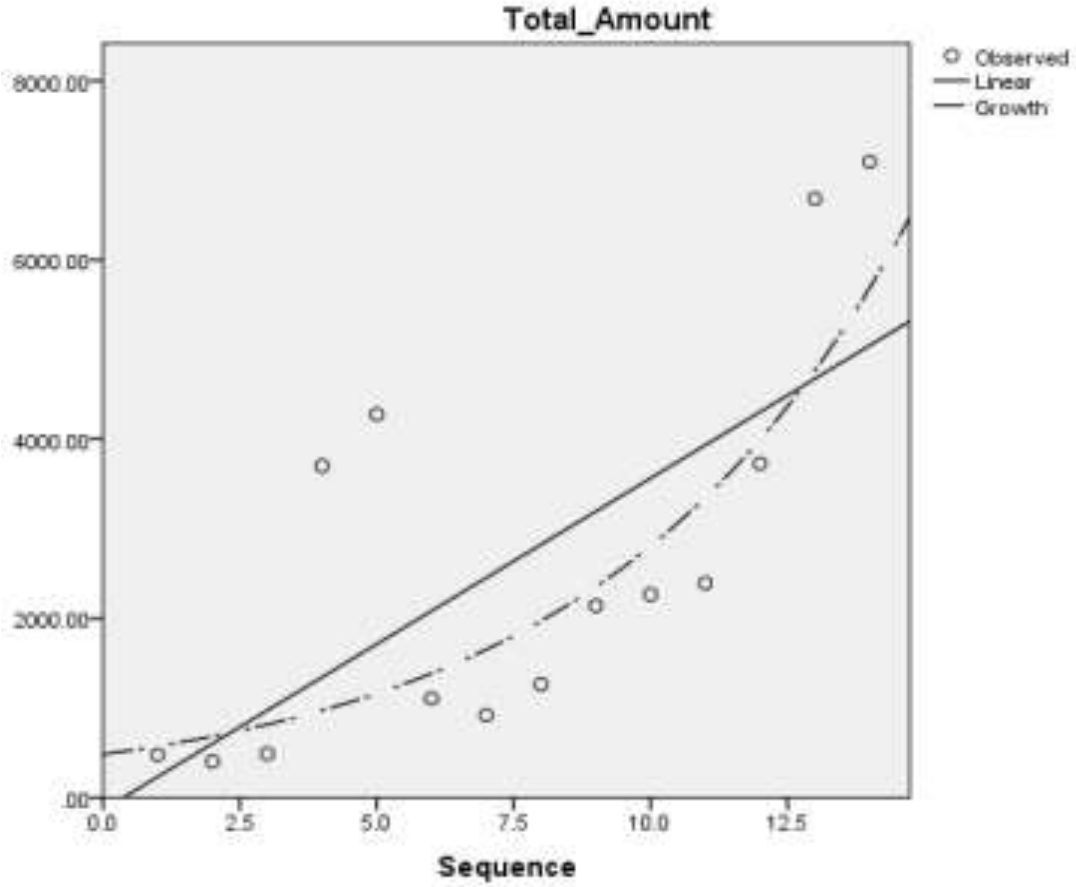

चित्र 4 : किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी राशि की वृद्धि दर का चित्रिय प्रदर्शन

2) संस्थानुसार किसान क्रेडिट कार्ड का विश्लेषण

संस्थानुसार किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन की प्रगति को देखें तो इसे तालिका 1 तथा चित्र 5 में प्रदर्शित किया जा रहा है। तालिका से स्पष्ट है कि 2006 से लेकर 2019 तक सहकारी बैंक तथा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक का हिस्सा कुल निर्गमन में क्रमशः बढ़ा है (कुछ उच्चावचन के साथ) परन्तु वाणिज्य बैंक का हिस्से में कमी आई है। यदि सहकारी बैंक द्वारा निर्गमित किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या को देखें तो यह 2006 में 25.98 लाख थी जो 2008 में गिरकर 20.91 लाख हो गई। 2009–10 में अत्यधिक तीव्र वृद्धि पाई और इसके द्वारा निर्गमन संख्या 378.88 लाख थी। जो पुनः 2011, 2012, 2013 में गिरती चली गई और 26.19 लाख पर पहुंच गई। पुनः इसमें वृद्धि का क्रम पाया गया और 2017 में यह बढ़कर 358.83 लाख हो गई। जो 2019 में गिरकर 304.14 लाख हो गई। औसतन 162.78 के बराबर सहकारी बैंक द्वारा कार्ड निर्गमित किये गये। इसी प्रकार क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक द्वारा निर्गमित किसान क्रेडिट कार्ड का निर्गमन रहा। औसतन 64.16 लाख किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक द्वारा निर्गमित किये। वाणिज्यिक बैंक का क्रम भी इसी अनुरूप देखा जा सकता है। जो औसतन 164.39 लाख पर किसान क्रेडिट कार्ड पर निर्गमित किया। इन तीनों ही संस्थाओं में सबसे ज्यादा उच्चावचन सहकारी बैंक में देखा जा सकता है। परन्तु संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर भी सहकारी बैंक की ही सबसे अधिक पाई गई जो 19.21 प्रतिशत के बराबर है। इसके उपरान्त क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक की समृद्धि दर 17.7 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक बैंक की 13.2 प्रतिशत रही। कुल समृद्धि दर 16.2 प्रतिशत पाई गई थी, सहकारी बैंक

एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर कुल संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से भी ऊँची पाई गई है। सहकारी बैंक द्वारा निर्गमित किसान क्रेडिट कार्ड का हिस्सा कुल निर्गमित किसान क्रेडिट कार्ड में देखा जाये तो 2006 में जहां 32.43 प्रतिशत था उच्चावचन के साथ 2019 में 45.87 प्रतिशत हो गया। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का हिस्सा 15.59 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 18.48 प्रतिशत हो गया। जबकि वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गमित किसान क्रेडिट कार्ड का हिस्सा कुल निर्गमित किसान क्रेडिट कार्ड में 2016 में जहां 51.98 था 2019 में गिरकर 35.64 रह गया।

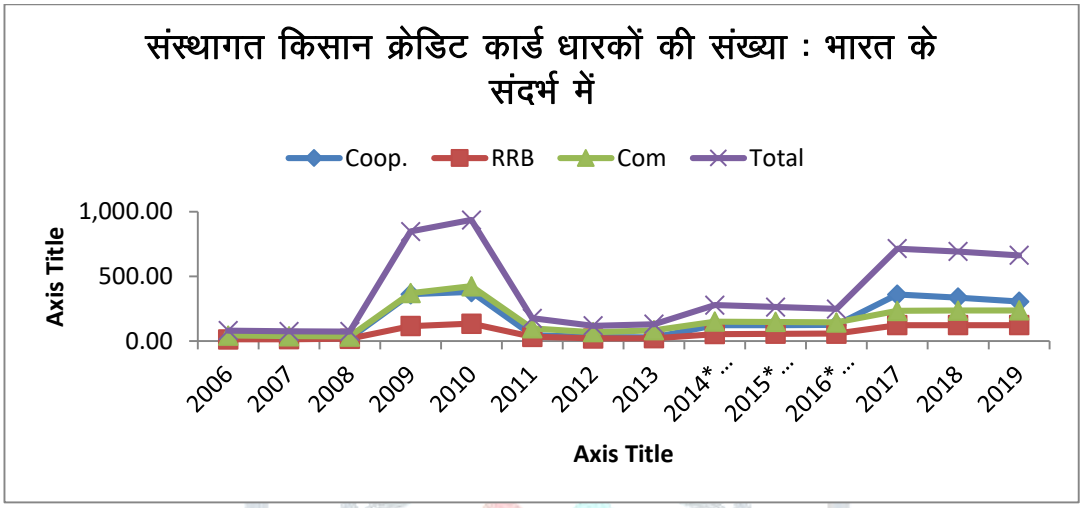

चित्र 5 : संस्थागत किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या : भारत के संदर्भ में

स्पष्ट है कि 2009 में किसान क्रेडिट कार्ड का निर्गमन अत्यन्त तीव्र गति से हुआ। वर्ष 2017 भी उच्चतम वर्ष के रूप में देखा जा सकता है। इन अवधियों में सबसे प्रमुख भूमिका प्रारम्भ में वाणिज्यिक बैंक की रही। परन्तु 2017, 2018, 2019 के आस–पास सहकारी बैंक में इस स्थिति को पलट दिया। वर्तमान में सहकारी बैंकों की भूमिका वित्तीय बैंकों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है।

मंजूरी राशि के आधार पर हम देखते हैं कि सहकारी बैंक, क्षेत्रिय ग्रामीण तथा वाणिज्यिक बैंक में क्रमशः लगातार वृद्धि हुई है। परन्तु सहकारी बैंक का हिस्सा 2006 से लेकर 2019 तक गिरा है। जबकि क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के हिस्से में कुछ उच्चावचन के साथ लगभग स्थिरता बनी रही है। परन्तु व्यापारिक बैंक के हिस्से में काफी वृद्धि पाई गई है। औसतन 609.17 अरब की राशि 2006 से 2019 तक सहकारी बैंक द्वारा मंजूरी की गई है। जबकि क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक द्वारा मात्र 417.06 अरब की मंजूरी राशि दी गई है। सबसे अधिक मंजूरी राशि व्यापारिक बैंक द्वारा औसतन 1611.71 अरब की दी गई है। संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर सहकारी बैंक की 14 प्रतिशत, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक की 21.22 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक बैंक की 25.57 प्रतिशत रही है। कुल मंजूरी राशि की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर अधिक रही है। (तालिका 5, चित्र 6)

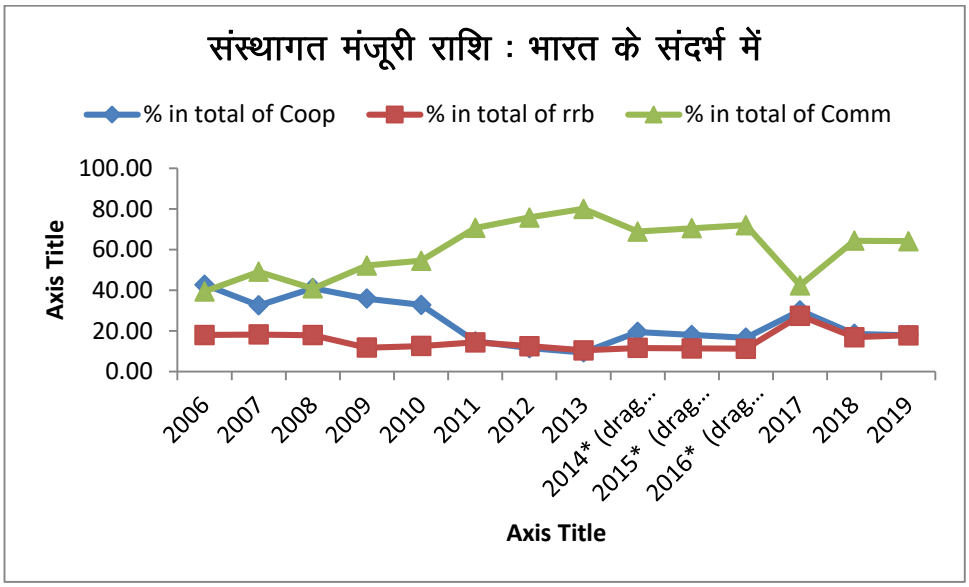

चित्र 6 : संस्थागत मंजूरी राशि : भारत के संदर्भ में

सहकारी बैंकों की मंजूरी राशि का कुल मंजूरी राशि में हिस्सा 2006 में जहां 42.73 प्रतिशत था वो न्यूनतम 9.44 प्रतिशत पर गिरकर 2013 में अत्यधिक कम हो गया। परन्तु 2017 में पुनः बढ़कर 30.10 प्रतिशत हो गया। तदुपरान्त 2019 में यह पुनः घटकर 17.96 प्रतिशत पर आ गया। क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक द्वारा मंजूरी राशि का कुल मंजूरी राशि में हिस्सा 2006 में जहां 18.3 प्रतिशत था 2009 में गिरकर 11.84 प्रतिशत हो गया। 2011 तक इसमें वृद्धि पाई परन्तु पुनः 2013 में यह गिरकर 10.50 प्रतिशत रह गया। तदुपरान्त बढ़ते घटते क्रम के बाद 2017 में यह 27.48 प्रतिशत हो गया जो 2019 में 17.91 प्रतिशत हो गया। वाणिज्यिक बैंक हिस्सा जहां 2006 में 39.45 प्रतिशत था घट–बढ़कर 2013 में 80.06 प्रतिशत हो गया। जो गिरकर 2019 में 64.11 प्रतिशत हो गया।

निष्कर्ष

निष्कर्षात्मक के रूप में कहां जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंक की भूमिका मंजूरी राशि में सर्वप्रथम रही तदुपरान्त सहकारी बैंक की भूमिका पाई जाती है। क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की भूमिका सबसे कम है। इसे चित्र 6. 4 में देखा जा सकता है।

समयानुसार किसान धारकों की संख्या कुछ उच्चावचन के साथ 2006 से 2019 तक बढ़ती रही है। आवश्यक अब तक 377.92 लाख किसान क्रेडिट भारतवर्ष में पाए जा रहे है। संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 16.29% के अनुसार धारकों की संख्या में वृद्धि पाई गई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 2006 से लेकर 2017 तक वाणिज्यिक बैंकों की रही है परंतु इसके उपरांत सहकारी बैंकों ने 2019 तक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया है। सहकारी बैंकों वाणिज्यिक एवं ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक को में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में कुछ उच्चावचन के साथ वृद्धि का क्रम पाया गया है। परंतु यदि कुल निर्गमन में इन बैंकों का हिस्सा देखा जाए तो सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हिस्से में वृद्धि हुई है (2006–2019 तक)। वाणिज्यिक बैंक के हिस्से में इसी

अवधि में कमी आई है। सहकारी बैंकों के द्वारा औसतन 2006 से 2019 तक की अवधि में 162.78 लाख, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 64.16 लाख तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 164.39 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का निर्गमन हुआ है। इसकी संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर क्रमश 19.2%, 17.7% एवं 13% रही है। सहकारी बैंकों का कुल निर्गमन में हिस्सा जहां 2006 में 32.43% या वह 2019 में बढ़कर 45.87% हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 15. 59% से समान अवधि में बढ़कर 18.48% हो गया। जबकि वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 51.98% से गिरकर 35. 64% रह गया।

समयानुसार मंजूरी राशि को देखें तो इसका क्रम भी निरंतर बढ़ने का पाया गया है परन्तु थोड़ा–सा 2009 से 2011 तक अधिक विस्तार मिलता है। औसतन 2637.89 बिलियन की मंजूरी राशि समस्त बैंकों द्वारा पूरे भारतवर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दी जा चुकी है। संयुक्त वार्षिक दर 21.28% पाई गई है। संस्थागत रूप से देखें तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका वाणिज्यिक बैंकों की रही है। मंजूरी राशि का निर्गमन (2006 से 2019 तक) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ज्यादा रहा है। तीनों ही बैंकों में 2006 से 2019 तक मंजूरी राशि की मात्रा क्रमशः बढ़ती रही है (कुछ उच्चावचन के साथ)। औसतन सहकारी बैंकों द्वारा 609.17 बिलियन राशि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 417.06 बिलियन राशि तथा वाणिज्यिक बैंक द्वारा 1161.71 बिलियन राशि निर्गमित की गई है इन की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 14%, 21.2% तथा 25.57% रही है। 2006 में कुल मंजूरी राशि में सहकारी बैंकों का हिस्सा 42.73% क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 18.03% तथा वाणिज्यिक बैंक 39.45% था। जो 2019 में सहकारी और क्षेत्रीय बैंक का हिस्सा गिरकर 17.96% तथा 17.91% रह गया है जबकि वाणिज्यिक बैंक का हिस्सा बढ़कर 64.13% हो गया।

यह देखा गया है कि क्रेडिट डिलीवरी तंत्र को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है। वितरण तंत्र पर्याप्त नहीं है क्योंकि कृषि को उद्योग बनाने के लिए कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कृषि का केवल एक कुशल और इष्टतम उत्पादन स्तर ही दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बनाए रख सकता है । इसलिए केसीसी के रूप में अल्पावधि ऋण तक किसानों की पहुंच को सुगम बनाने के संबंध में विभिन्न पहलों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर उचित नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता है ।

ग्रन्थ–सूची

- RBI (Various report), "Report of Trend and Progress of Banking in India".
- Patil, R. D. (2014). Role of Commercial Banks in Financial Inclusion through Kisan Credit Card Scheme in India. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 3(5)(4), 31-46.
- Datt. Rudra and Sundaram, K.P.M. (2016) 'Indian economy' S.Chand Publication New Delhi.
- Gandhimathi, S., Sumaiya, M. (2015). Role of Kisan Credit Card System in the Distribution of Agricultural Credit in India. International Journal in Management and Social Science, 3(2), 464-472.
- Gupta, A.K; Rao, V.K and Singh, J (1998) "Study on co-operative credit as on aid to increase agricultural production" Indian Journal of Agricultural Economics, 22 (2):367
- Loganathan,P (2008) "Kisan credit cards (KCCs): a boon for small farmers" IndianCooperative-Review 45(4): 300-304.
- अग्रवाल एन एल0 'भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र' हिन्दी अकादमी, जयपुर।